आर. एन. आई. नं. UPHIN/2010/32566 डाक. पंजीयन. संख्या– SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक
हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 17 अंक : 14 लखनऊ, मंगलवार 14 जुलाई 2026 सा 20 जुलाई 2026 तक पृष्ठ–8 मूल्य : एक रूपया

राम मंदिर चंदा चोरीः सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को भेजा नोटिस, SIT से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (१३ जुलाई) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को एक नोटिस जारी किया। यह नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान की कथित चोरी की निष्पक्ष और तय समय–सीमा के भीतर जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर जारी किया गया। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने उत्तर प्रदेश की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को दान की कथित चोरी के मामले में अपनी जांच की प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र और राज्य की ओर से पेश हुए, ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई २० जुलाई को होगी, जब कोर्ट याचिकाओं पर विचार करेगा और SIT की जांच के नतीजों की समीक्षा करेगा। तीन याचिकाकर्ताओं में से एक, नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की CBI जांच की मांग की। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की CAG (कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) से ऑडिट कराने की भी मांग कीय यह ट्रस्ट राम मंदिर के कामकाज का प्रबंधन करता है। अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने

भी ऐसी ही मांग करते हुए दूसरी याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग के अलावा, RJD सांसद सुध ाकर सिंह द्वारा दायर तीसरी याचिका में मंदिर ट्रस्ट के पूरे वित्तीय कामकाज की फ रेंसिक ऑडिट की मांग की गई है। जून के पहले हफ्ते में राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान गड़बड़ी की बात सामने आने पर मंदिर के दान के कथित दुरुपयोग का मामला प्रकाश में आया। मंदिर ट्रस्ट की सिफारिश पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई। SIT में लखनऊ डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किरण एस और स्पेशल सेक्रेटरी (फाइनेंस) नील रतन शामिल हैं। SIT को गबन के शुरुआती सबूत मिले, जिसके बाद FIR दर्ज की गई। अब तक, इस मामले में मंदिर की दान–गिनती प्रक्रिया से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। SIT के अनुसार, ४५ दिनों की CCTV फुटेज में इन प्रक्रियाओं का बार–बार उल्लंघन देखा गया। जांचकर्ताओं का आरोप है कि आरोपियों ने गिनती ह ल के अंदर कैश की आवाजाही पर कमजोर निगरानी और अपर्याप्त जांच का फायदा उठाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान कम से कम ७० बार चोरी हुई। इसमें जांच से पहले कुछ कर्मचारियों से लगभग ७८.६४ लाख रुपये और गिनती वाले कमरे से जुड़े बाथरूम से २. २५ लाख रुपये बरामद होने का भी जिक्र है।

UP को Nitin Gadkari की सौगात, North&South Connectivity के लिए ६०,००० करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट मंजूर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के लिए ५०,०००–६०,००० करोड़ रुपये के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इनमें उत्तर–दक्षिण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। ४,८५० करोड़ रुपये से ज्यादा के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि नई मंजूरियों में पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के लिए बाईपास और राज्य के हर जिला मुख्यालय तक चार–लेन कनेक्टिविटी शामिल है। आदित्यनाथ ने कहा कि आज गडकरी ने ५०,०००–६०,००० करोड़ रुपये के रोड प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, गंगा, बुंदेलखंड, आगरा–लखनऊ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए पहले से ही बेहतरीन ईस्ट–वेस्ट कनेक्टिविटी है, लेकिन अब न र्थ–साउथ कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नए इलाकों की पहचान की गई है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के लिए बाईपास और राज्य के हर जिला मुख्यालय तक फोर–लेन कनेक्टिविटी को भी मंजूरी दी है। गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का शुक्रिया अदा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मंजूरियों से उत्तर प्रदेश का रोड नेटवर्क मजबूत होगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में राज्य में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दस साल पहले उत्तर प्रदेश पहचान के संकट से जूझ रहा था। न तो कोई नीति थी और न ही कोई दिशा। राज्य दंगों और माफिया राज का पर्याय बन गया था और इसे श्बीमारूश राज्यों में गिना जाता था।९ आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आज उत्तर प्रदेश श्बीमारूश राज्य नहीं रहा। यह भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन गया है। उन्होंने इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश अच्छे शासन, बेहतर सुरक्षा और विश्व–स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक मिसाल बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब सड़कों, रेलवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों और इनलैंड व टरवे (आंतरिक जलमार्ग) का एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। गडकरी की तारीफ करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में नितिन गडकरी की डिक्शनरी में 'नहीं' शब्द का कोई स्थान नहीं है।

अब बीमारू नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का विकास इंजन है उत्तर प्रदेश : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि प्रदेश ने बीते एक दशक में विकास की नई पहचान बनाई है और अब वह बीमारू राज्य नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का 'ग्रोथ इंजन' बन चुका है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के लिए ५० से ६० हजार करोड़ रुपये की नई सड़क अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे प्रदेश का सड़क नेटवर्क और अधिक मजबूत होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ४,८५० करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्वांचल, गंगा, बुंदेलखंड, आगरा–लखनऊ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्व–पश्चिम संपर्क पहले ही मजबूत हो चुका है। अब उत्तर–दक्षिण संपर्क को बेहतर बनाने के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बाईपास निर्माण और प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को फोरलेन सड़क से जोड़ने की योजनाओं को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से निवेश, व्यापार और रोजगार को नई गति मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक दशक पहले उत्तर प्रदेश पहचान के संकट से जूझ रहा था। प्रदेश दंगों, माफिया राज और खराब कानून–व्यवस्था के कारण बीमारू राज्यों में गिना जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और डबल इंजन सरकार की नीतियों के चलते आज उत्तर प्रदेश सुशासन, बेहतर सुरक्षा और विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचे का मॉडल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क, रेल, मेट्रो, हवाई अड्डों और अंतर्देशीय जलमार्गों को जोड़ते हुए एकीकृत परिवहन नेटवर्क विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी ने देश में सड़क अवसंरचना को नई दिशा दी है और उनके प्रयासों से वाराणसी–हल्दिया के बीच देश का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग भी शुरू हुआ।

योगी ने ६३ किलोमीटर लंबे लखनऊ–कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे दोनों महानगरों के बीच यात्रा आसान होगी और प्रस्तावित स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) को भी मजबूती मिलेगी। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ को बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली जैसे जिलों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, 'यह केवल एक एक्सप्रेसवे नहीं, बल्कि ऐसा विकास मार्ग है जो प्रदेश की रफ्तार बढ़ाएगा, प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और भविष्य की समृद्धि के नए द्वार खोलेगा।' मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद प्रदेश में आधारभूत ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा परिचालित एक्सप्रेसवे नेटवर्क विकसित करने वाला राज्य बन चुका है। साथ ही यहां विशाल रेलवे नेटवर्क, कई मेट्रो परियोजनाएं और तेजी से बढ़ती हवाई सेवाएं प्रदेश को नई आर्थिक ताकत प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग और सरकार की विकासोन्मुख नीतियों ने उत्तर प्रदेश की बीमारू राज्य वाली छवि को समाप्त कर उसे भारत की अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बना दिया है।

सम्पादकीय

स्कूलों पर ताला, भविष्य पर सवालः क्या शिक्षा अब 'संसाधन प्रबंधन' का विषय भर रह गई है?

भारत जैसे युवा आबादी वाले देश में शिक्षा का विस्तार राष्ट्रीय प्राथमिकता होना चाहिए। लेकिन पिछले एक दशक के आंकड़े एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार २०१४–१५ से २०२४–२५ के बीच देश में लगभग ६४ हजार सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल बंद हो गए। इसका अर्थ है कि औसतन प्रतिदिन २५ स्कूलों पर ताला लगा। इसी अवधि में भारत की जनसंख्या १२.३ करोड़ बढ़ी, लेकिन सरकारी स्कूलों की संख्या घट गई। यह विरोधाभास केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि नीति और प्राथमिकताओं का भी है। केंद्र सरकार ने 'संसाधनों के उपयोग में सुधार' के उद्देश्य से स्कूल समेकन की नीति अपनाई। तर्क यह था कि कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का विलय कर संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाएगा। लेकिन शिक्षा केवल प्रशासनिक दक्षता का विषय नहीं हैय यह सामाजिक न्याय और समान अवसर का भी आधार है। जब गांव या कस्बे का स्कूल बंद होता है, तो उसके साथ कई बच्चों की शिक्षा की राह भी कठिन हो जाती है। विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए दूर स्थित स्कूल तक पहुंचना आसान नहीं होता। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की क्षमता पर पड़ता है। रिपोर्ट बताती है कि प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर अपेक्षाकृत कम है, लेकिन अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सेकेंडरी स्तर से पहले पढ़ाई छोड़ने की दर ११.५ प्रतिशत तक पहुंच जाना इस बात का संकेत है कि शिक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर संरचनात्मक कमी है। यदि विद्यालय तक पहुंच ही कठिन हो जाए, तो शिक्षा का अधिकार व्यवहार में कमजोर पड़ जाता है। गुणवत्ता का संकट भी उतना ही गंभीर है। नौवीं कक्षा तक पहुंचने के बावजूद यदि बड़ी संख्या में छात्र प्रतिशत, भिन्न और अनुपात जैसी बुनियादी अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते, तो यह केवल विद्यार्थियों की नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था की चुनौती है। विद्यालयों की संख्या घटने और सीखने के स्तर में गिरावट का यह दोहरा संकट भविष्य के भारत के लिए चिंता का विषय है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षा को लागत या संसाधन बचत के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। विद्यालय केवल भवन नहीं होतेय वे सामाजिक परिवर्तन, समान अवसर और लोकतांत्रिक चेतना के केंद्र होते हैं। यदि शिक्षा तक पहुंच सीमित होगी और उसकी गुणवत्ता कमजोर पड़ेगी, तो विकसित भारत का सपना भी अधूरा रह जाएगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा नीति का मूल्यांकन केवल वित्तीय दक्षता से नहीं, बल्कि इस आधार पर किया जाए कि क्या हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वास्तव में पहुंच रही है। क्योंकि जिस देश की प्राथमिक शिक्षा मजबूत नहीं होती, वह ज्ञान, विज्ञान और नवाचार की वैश्विक दौड़ में स्थायी नेतृत्व की कल्पना भी नहीं कर सकता। शिक्षा पर किया गया निवेश खर्च नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य में किया गया सबसे बड़ा निवेश है।

लखनऊ सिविल कोर्ट को छह जिलेटिन बम से उड़ाने की धमकी, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के रजिस्ट्रार की आईडी पर आया धमकी का मेल

लखनऊरू सिविल कोर्ट को सोमवार दोपहर छह जिलेटिनबॉम से उड़ाने की धमकी दी गई। यह धमकी हाईकोर्ट लखनऊ पीठ के रजिस्ट्रार की आईडी पर मेल भेजकर दिया गया था। जानकारी होने पर पुलिस ने पूरे परिसर में डॉग और बम स्क्वायड दस्ते की मदद से करीब दो घंटे तक चेकिंग की। कोई भी संदिग्ध वस्तु न मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी भरा मेल सोमवार दोपहर १२ बजकर १६ मिनट ४८ सेकेंड पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के रजिस्ट्रार की अधिकारिक मेल आईडी पर आया। मेल में लिखा था कि जल्द से जल्द सिविल कोर्ट परिसर को खाली करा लें। सिर्फ बिल्डिंग का नुकसान करना है। दोपहर करीब दो बजे छह जिलेटिन बम से विस्फोट किया जाएगा। कोर्ट से सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर वजीरगंज राजेश कुमार त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ पहुंचे। डाग व बम स्क्वायड दस्ता बुलाया गया। कोर्ट परिसर के सभी कक्षों, पार्किंग व बरामदे में सघन चेकिंग अभियान चला। हैंड हेल्ड डिटेक्टर से फर्नीचर के नीचे चेकिंग की

गई। हालांकि कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद पुलिस और कोर्ट कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। इंस्पेक्टर वजीरगंज राजेश त्रिपाठी के मुताबिक तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। धमकी भरा मेल प्रबाजानी लखनवी की आईडी से आया था। उसके बारे में जांच की जा रही है। साइबर क्राइम सेल को जांच में लगाया गया है। इस संबंध में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्टदर्ज कर लिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट पर इससे पहले भी धमकी भरे ई–मेल भेजे जा चुके हैं। १३ फरवरी को दोपहर १रू१० बजे जिला जज की आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसा ही एक ई–मेल आया था। इसके तीन दिन बाद १६ फरवरी को फिर ठीक १:१० बजे डिस्ट्रिक्ट जज की आधिकारिक वेबसाइट पर धमकी भरा ई–मेल भेजा गया। उस मामले में कोर्ट के नाजिर जितेंद्र राय ने ई–मेल एड्रेस के आधार पर वजीरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच साइबर क्राइम को सौंपी गई थी, लेकिन करीब साढ़े चार महीने बीतने के बाद भी ई–मेल भेजने वालों का सुराग नहीं लग सका है। एडीसीपी धनंजय कुशवाह ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

69वीं वैज्ञानिक प्रतियोगिता का आगाज, फोरेंसिक से डॉग स्क्वायड तक होगा कौशल परीक्षण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी और वैज्ञानिक कार्यकुशलता को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित ६९वीं वार्षिक वैज्ञानिक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसकी शुरूआत सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन्स परिसर में किया गया। इसमें अनुसंधान, पुलिस फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कंप्यूटर, डॉग स्क्वाड एवं एंटी सेबोटाज चेक की प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता में १२ जोन के १३५ पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। चार दिवसीय इस प्रतियोगिता का समापन १६ जुलाई को होगा। उद्घाटन समारोह में डीसीपी लाइंस अनिल कुमार यादव, अपर डीसीपी लाइंस राजेश कुमार यादव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के तहत कंप्यूटर, फोरेंसिक साइंस, पुलिस फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी,

डॉग स्क्वाड और एंटी सेबोटाज चेक समेत विभिन्न विधाओं में प्रतिभागियों की तकनीकी दक्षता का परीक्षण किया जाएगा। पहले दिन फोरेंसिक साइंस की लिखित परीक्षा और घटना स्थल निरीक्षण प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्य अतिथि अपर्णा कुमार ने कहा कि यह प्रतियोगिता केवल प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं, बल्कि पुलिसिंग में प्रोफेशनल एक्सीलेंस को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम है। बदलते दौर में साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे तकनीकी अपराधों से निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और आधुनिक तकनीक में दक्षता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज की पुलिसिंग प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती जा रही है। उन्होंने प्रतिभागियों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनुशासन और टीम भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि यहां से मिले नए अनुभव और तकनीकी ज्ञान का उपयोग अपने–अपने कार्यक्षेत्र में करें। अधिकारियों के अनुसार, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य पुलिस बल में वैज्ञानिक सोच, तकनीकी उत्कृष्टता और व्यावसायिक दक्षता को बढ़ावा देना है, जिससे अपराधों की वैज्ञानिक विवेचना, साक्ष्य संकलन और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

६८५०० सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम की मांग उठाई

लखनऊ। ६८,५०० सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा–२०१८ के परिणाम में संशोधन और उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश लागू करने की मांग को लेकर सोमवार को अभ्यर्थियों ने प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने आयोग की संस्तुति के अनुरूप कार्रवाई कर संशोधित परिणाम जारी करने की मांग की। मामले की पैरवी कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने हाल ही में ६८,५०० सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा–२०१८ से जुड़े प्रकरण में ओबीसी अभ्यर्थियों को अर्हता अंक में पांच प्रतिशत की छूट दिए जाने संबंधी निर्णय को बरकरार रखा है। आयोग ने ५ जनवरी २०२२ को जारी अपनी संस्तुति को पुनः प्रभावी रखने का फैसला किया है। साथ ही आरक्षण नियमों का पालन नहीं

करने वाले अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। आयोग के अनुसार, ६८,५०० सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा–२०१८ में ओबीसी अभ्यर्थियों को १५० अंकों में से ६० अंक, यानी ४० प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उत्तीर्ण माना जाए। आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा परिणाम में संशोधन कर सफल अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराई जाए। इसी मांग को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सीतापुर से आशुतोष वर्मा, प्रतापगढ़ से अखिल यादव, गोरखपुर से विमलेश गुप्ता, संतकबीर नगर से दुर्गा प्रसाद, मेरठ से रेखा वर्मा, एटा से पंकज गोस्वामी, ललितपुर से शिशुपाल सिंह लोधी, आगरा से काशिफ हुसैन, वाराणसी से पंकज मौर्य, हरदोई से सुधीर विश्वकर्मा, बिजनौर से सत्यवती नगर और कुशीनगर से राकेश साहनी के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

वृक्षारोपण महायज्ञ-2026

बीआरसी इटौंजा में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम, अशोक, सइजन, मीठीनीम और इमली के पौधे रोपे गए

संवाददाता लखनऊ। प्रदेशव्यापी वृक्षारोपण महायज्ञ–२०२६ एवं 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत विकासखंड बक्शी का तालाब (बीकेटी) स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) इटौंजा में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया तथा उनके संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत इटौंजा के अध्यक्ष अवधेश कुमार अवस्थी, खंड शिक्षा अधिकारी बीकेटी प्रीती शुक्ला, शैल सिंह राठौर एवं अनुराग सिंह राठौर ने संयुक्त रूप से अशोक, सहजन, मीठी नीम और इमली के पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर शैल सिंह राठौर के ७५वें जन्मदिवस को यादगार बनाते हुए 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत विशेष रूप से एक पौधा रोपा गया। उपस्थित सभी लोगों ने पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण का संकल्प लेते हुए पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन का आधार हैं। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान प्रेंति और मातृत्व के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ–साथ समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने का सशक्त माध्यम बन रहा है। इस अवसर पर अंकित अवस्थी, आलोक राय, कन्हैया कुमार क्रांति, ओमप्रकाश सहित अनेक गणमान्य नागरिक, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने प्रदेश को हरित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में सक्रिय योगदान देने का संकल्प दोहराया।

- शैल सिंह राठौर के ७५वें जन्मदिवस रोपा गया 'एक पेड़ माँ के नाम' पौधा
- सभी नें ली पेड़ों के संरक्षण की शपथ
- पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान से जुड़ा अर्पण फाउंडेशन, पदाधिकारियों ने किया वृक्षारोपण और दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

संवाददाता लखनऊ। 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत अर्पण फाउंडेशन के कार्यालय परिसर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष आरती पाण्डेय, सचिव अद्भुत पाण्डेय एवं कोषाध्यक्ष रिद्धिमा पाण्डेय ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आरती पाण्डेय ने कहा कि 'वृक्ष प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ जीवन देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उनका संरक्षण और नियमित देखभाल भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।' संस्था के सचिव अद्भुत पाण्डेय ने कहा कि 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान प्रकृति और मातृत्व के सम्मान का प्रतीक है। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ के नाम एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित रखने का संकल्प ले, तो पर्यावरण संरक्षण का यह अभियान एक व्यापक जनआंदोलन बन सकता है।' कोषाध्यक्ष रिद्धिमा पाण्डेय ने कहा कि 'बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वृक्षारोपण सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। हमें केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हरित और स्वच्छ वातावरण मिल सके।' इस अवसर पर संस्था के संस्थापक ने कहा कि 'सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी केवल सेवा कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज को जागरूक करना भी उनका महत्वपूर्ण दायित्व है। वृक्षारोपण के माध्यम से हम प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की नींव रख सकते हैं।' कार्यक्रम के अंत में सभी पदाधिकारियों एवं उपस्थित सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने का संकल्प लिया। अर्पण फाउंडेशन ने भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण और जनजागरूकता से जुड़े ऐसे सामाजिक अभियानों को निरंतर जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया।

बिखरे रहे पारिवारिक और समाजिक संबंध सिमटता परिवार, निपटते रिश्ते, सिसकता अकेले

लखनऊ। संयुक्त परिवार की व्यवस्था से अलग आज एकल परिवार में सदस्यों को संबल देने वालों का अकाल सा है, ऐसे में रिश्ते टूट और बिखर ज्यादा रहे हैं। व्यक्ति तनाव और अवसाद का शिकार हो रहे हैं। ये कहना था मुख्य अतिथि राम कथा वाचक धीरेन्द्र वशिष्ठ का। उन्होंने कहा कि समाज मनुष्य को भ्रष्ट करता है मनुष्य अबोध बालक के रूप में जनम लेता है। जो स्वभाव से सरल और सीधा होता है। समाज में आने के बाद संपत्ति, लालच और ऊंच–नीच की भावना उसका स्वभाव परिवर्तित करके भ्रष्ट बना देती है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है।'परिवारिक और सामाजिक संबंधों का वर्तमान स्वरूप' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन अवध फाउण्डेशन की ओर से जानकीपुरम कार्यालय सभागार सभागार में किया गया था। अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्था के अध्यक्ष सूरजदेव शुक्ल ने कहा कि वर्तमान परिवेश में सतयुग से कलियुग तक पारिवारिक संबंधों का निरंतर पतन होता गया। इसे सुधारने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन करने के पश्चात बीना मिश्रा के शिष्यों अराध्या मिश्रा, अद्वैत मिश्रा, साक्षी मिश्रा, रचित मिश्रा द्वारा के श्रीराम स्तुति व हनुमान चालीसा के पाठ से हुआ। रामप्रकाश त्रिपाठी के संचालन में डॉ काशीनाथ पांडेय ने कहा परिवार के बिना शिक्षा, ज्ञान, विकास किसी बच्चे का नहीं हो सकता। प्राचीन भारतीय संस्कृति सभी अपने कर्तव्य बताती थी, लेकिन प्रदूषित पाश्चात्य संस्कृति अधिकार सिखा रही है, जो पतन का कारण है।बीना मिश्रा ने रामायण के चरित्रों को काव्य में ढालकर परिवार का महत्व बताया। बीरेन्द्र श्रीवास्तव ने समाज और देश की ईकाई परिवार को बताया।कार्यक्रम में शिक्षाविद्, समाजसेवी, बुद्धिजीवी और युवाओं के संग काशीनाथ पाण्डेय, आरडी शुक्ला, शिवकुमार पांडेय, छठ कुमार शुक्ला, आर सी त्रिपाठी, जानकी शरण शुक्ला, प्रणव दत्ता, प्रकाश चन्द्र शर्मा जी,राकेश तिवारी, केसर सिंह, बीना मिश्रा, राम दयाल शुक्ला, शिवकुमार पांडेय, जानकी शरण शुक्ला, टीएन शुक्ला, लक्ष्मी नारायण दीक्षित ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

लखनऊ के हाईकोर्ट परिसर में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत हुआ वृहद पौधरोपण

लखनऊ। 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत शनिवार को गोमती नगर स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ परिसर में वृहद पौधरोपण जन–महाअभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधरोपण कार्यक्रम में हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजन रॉय एवं अन्य न्यायमूर्तिगण ने सहभागिता की। उनके साथ न्यायालय के वरिष्ठ निबंधक, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण ने चांदनी, कनेर, गार्डेनिया, हरश्रृंगार, एवं गुलाचीन इत्यादि पौधों की अलग–अलग प्रजातियों का रोपण किया। यह कार्यक्रम वन विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य माँ के नाम पर एक पेड़ लगाकर स्थायी स्मृति स्थापित करना है, जो न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि हरित एवं समृद्ध भविष्य के निर्माण में भी योगदान देगा।

- वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजन र य समेत न्यायमूर्तिगण, अधिकारियों व अधिवक्ताओं ने रोपे चांदनी, कनेर, हरश्रृंगार के पौधे

योगी सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, १२ घंटे में ३६३ PCS अधिकारियों के तबादले

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए योगी सरकार ने महज १२ घंटे के भीतर ३६३ प्रांतीय सिविल सेवा **(PCS)** अधिकारियों का तबादला कर दिया। यह हाल के वर्षों का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। पहले चरण में १८२ अधिकारियों की सूची जारी की गई, जबकि कुछ घंटों बाद १८१ उपजिलाधिकारियों **(SDM)** की दूसरी ट्रांसफर सूची भी जारी कर दी गई। इस व्यापक तबादला अभियान के बाद प्रदेश के कई जिलों और तहसीलों में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह बदल गई है। बड़ी संख्या में एसडीएम के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं, वहीं कई अधिकारियों को विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों और विशेष कार्याधिकारी **(OSD)** जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी ट्रांसफर सूची में अयोध्या सबसे अधिक चर्चा में रहा, जहां आठ अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया। नगर निगम के सहायक आयुक्त अशोक कुमार गुप्ता समेत कई अधिकारियों को सोनभद्र, मथुरा, मैनपुरी, शामली,

बलिया, श्रावस्ती और मुरादाबाद में नई तैनाती मिली। इसके अलावा ललितपुर, गाजीपुर, वाराणसी, सहारनपुर, मथुरा, आगरा, बांदा, जौनपुर, गोरखपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर और अन्य जिलों के कई एसडीएम का भी स्थानांतरण किया गया। कई अधिकारियों के दायित्व बदलते हुए उन्हें विकास प्राधिकरणों और प्रशासनिक इकाइयों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले चरण में जारी १८२ अधिकारियों की सूची में ५४ महिला अधिकारी भी शामिल थीं। इनमें सुरभि शर्मा, प्रतिभा मिश्रा, गोपाल शर्मा, पुष्पेंद्र पटेल, मिथिलेश तिवारी और लवगीत कौर सहित कई अधिकारियों की नई तैनाती की गई। सूत्रों के अनुसार यह व्यापक प्रशासनिक फेरबदल आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों, कानून–व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार के उद्देश्य से किया गया है। लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित करने के साथ–साथ उनकी कार्यप्रणाली और प्रदर्शन के आधार पर भी नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। प्रदेशभर में जारी इस मेगा ट्रांसफर लिस्ट की व्यापक चर्चा है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसका असर प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

‘एक पेड़ माँ के नाम ३.०’ अभियान के तहत बेसिक विद्यालय अलीनगर सुनहरा में हुआ वृक्षारोपण, प्रधानाध्यापक बोले पेड़ हैं जीवन और भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी

लखनऊ। प्रदेशव्यापी ‘एक पेड़ माँ के नाम ३.०’ अभियान के अंतर्गत परिषदीय बेसिक विद्यालय अलीनगर सुनहरा में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में आम, पपीता, नीम और अमरूद के पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में प्रभारी प्रधानाध्यापक राकेश कुमार पाण्डेय, शिक्षामित्र सुनीता यादव तथा विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्ष श्रीमती पप्पी राजपूत ने संयुक्त रूप से पौधारोपण किया। इसके साथ ही सभी ने लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर प्रभारी प्रधानाध्यापक राकेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि पेड़ केवल हमें अक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि स्वच्छ पर्यावरण, शुद्ध वायु, वर्षा, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का आधार भी हैं। यदि आज हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और उनका संरक्षण करेंगे, तभी पर्यावरण संतुलित रहेगा और पृथ्वी को प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाया जा सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल अपनी जिम्मेदारी समझकर करनी चाहिए। उन्होंने

विद्यार्थियों को वृक्षों के महत्व से अवगत कराते हुए प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया और सभी से ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिवार एवं उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और अधिक से अधिक पौधे लगाकर उन्हें सुरक्षित रखने का संदेश दिया। विद्यालय परिसर में लगाए गए पौधे भविष्य में हरित वातावरण के निर्माण के साथ विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

४ अगस्त से होगा क्रिकेट का महासंग्राम, पहली बार लखनऊ और कानपुर में खेला जाएगा सीजन-४

लखनऊ। उत्तर प्रदेश क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी टी२० लीग सीजन–४ का आयोजन १४ अगस्त से ६ सितंबर २०२६ तक किया जाएगा। २४ दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल ३४ मुकाबले खेले जाएंगे। इनमें १३ डबल–हेडर मैचडे और ८ सिंगल–हेडर मैचडे शामिल होंगे। इस बार लीग अपने इतिहास में पहली बार दो शहरों में

आयोजित की जाएगी। टूर्नामेंट का पहला चरण भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में खेला जाएगा, जहां १३ मैचडे में कुल २२ मुकाबले होंगे। इसके बाद प्रतियोगिता ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर शिफ्ट होगी, जहां शेष १२ मैच ११ मैचडे में आयोजित किए जाएंगे। सीजन–४ का उद्घाटन समारोह और पहला मुकाबला लखनऊ में होगा, जबकि फाइनल मुकाबला और समापन समारोह कानपुर में आयोजित किया जाएगा। रविवार को हुई उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन **(UPCA)** की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लीग के चौथे संस्करण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में टूर्नामेंट के शेड्यूल, आयोजन स्थलों, प्लेयर अक्शन, संचालन व्यवस्था, प्रतिभा विकास और प्रतियोगिता से जुड़े अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर यूपीसीए ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला के खेलों के विकास के लिए लगातार मिल रहे मार्गदर्शन, सहयोग और समर्थन के प्रति आभार व्यक्त किया। सीजन–४ के लिए २४ जुलाई को आगरा में मिनी अक्शन आयोजित किया जाएगा। लीग की छह फ्रेंचाइजियों में कुल ४५ खिलाड़ी स्लट उपलब्ध रहेंगे। गवर्निंग काउंसिल ने रिटेंशन पॉलिसी, प्लेयर चयन प्रक्रिया, कैचमेंट एरिया ट्रायल्स, सपोर्ट स्टाफ चयन दिशा–निर्देश और मिनी अक्शन नियमावली को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पूरे टूर्नामेंट में पारदर्शिता, निष्पक्षता और उच्च पेशेवर मानकों को बनाए रखना है। यूपी टी२० लीग में इस बार भी कैचमेंट एरिया मडल लागू रहेगा। इसके जरिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के उभरते क्रिकेटरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर अवसर मिलेगा और स्थानीय टैलेंट को बढ़ावा मिलेगा। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना इस सीजन में भी यूपी टी२० लीग के ब्रांड एंबेसडर बने रहेंगे। लीग का लोकप्रिय आधिकारिक एंथम खिलाड़ी यहाँ बनता है भी इस संस्करण में जारी रहेगा। लीग में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीमों और खिलाड़ियों के लिए कुल ३ करोड़ रुपये का प्राइज पूल रखा गया है। विजेता टीम को १ करोड़ रुपये, जबकि उपविजेता को ६० लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाली टीमों और खिलाड़ियों को भी आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।

मकान और प्लॉट दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

लखनऊ। कृष्णानगर पुलिस ने मकान और प्लॉट दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के तीन पुरुष और एक महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह लोगों को सस्ते दाम पर मकान, प्लॉट और अन्य संपत्ति दिलाने का लालच देकर उनसे अग्रिम रकम वसूलता था। रुपये लेने के बाद न तो संपत्ति दिलाता था और न ही रकम लौटाता था। विरोध करने पर पीड़ितों को धमकियां भी दी जाती थीं। इंस्पेक्टर कृष्णानगर पीके सिंह के मुताबिक रविवार को माता जी की बगिया क्षेत्र से आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में पहले से दर्ज मामले में कई धाराएं बढ़ाते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, एलडीए कॉलोनी निवासी विनय कुमार पांडेय की तहरीर पर २५ अप्रैल २०२५ को कृष्णानगर थाने में मामला दर्ज हुआ था। आरोप था कि अमन शुक्ला समेत १३ लोगों ने मकान दिलाने के नाम पर उनसे रुपये ऐंठ लिए और बाद में जान–माल की धमकी देने लगे। गिरफ्तार आरोपियों में एलडीए कॉलोनी निवासी सुनील शुक्ला, सुनीता शुक्ला, आशियाना निवासी पंकज अग्रवाल तथा आलमबाग निवासी दीपक उर्फ दिवाकर राय शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गिरोह बनाकर भोले–भाले लोगों को कम कीमत में जमीन, मकान और प्लॉट दिलाने का झांसा देते थे। भरोसा जीतने के बाद एडवांस रकम ले लेते और फिर संपर्क खत्म कर देते थे। ठगी से मिली रकम गिरोह के सदस्य आपस में बांट लेते थे। पहचान छिपाने के लिए अलग–अलग मोबाइल नंबर, बैंक खाते और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और ठगी की अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। इंस्पेक्टर पीके सिंह के मुताबिक गिरोह का सरगना अमन शुक्ला है। उसके खिलाफ आशियाना व सरोजनीनगर में चार मामले दर्ज हैं। वहीं, सुनीता शुक्ला व दिवाकर राय के खिलाफ भी मामले दर्ज है। पुलिस फरार अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल के १६वें दिन सोनम वांगचुक का ८.२ किलो घटा वजन, गिरा शुगर लेवल

नई दिल्ली। 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने सोमवार को कहा कि शिक्षाविद और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का वजन जंतर-मंतर पर अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल शुरू करने

के बाद से ८.२ किलोग्राम कम हो गया है। पार्टी ने यह भी बताया कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल गिरकर **67 mg/dL** हो गया है और केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर जवाब देने की अपील की। वांगचुक के अनशन का १६वां दिन होने पर सीजेपी ने कहा कि उनकी सेहत और बिगड़ गई है। परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर पार्टी का विरोध प्रदर्शन सोमवार को २४वें दिन में प्रवेश कर गया, जबकि विपक्षी नेताओं और छात्र समूहों का समर्थन प्रदर्शन स्थल पर जारी रहा। सीजेपी की ओर से जारी हेल्थ अपडेट के मुताबिक, वांगचुक का ब्लड प्रेशर **107/70 mm Hg** रिकॉर्ड किया गया। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने सरकार से अपील की कि वे इस मामले को अहंकार की लड़ाई न बनने दें। दिपके ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वांगचुक की भूख हड़ताल का १६वां दिन है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इसे अहंकार की लड़ाई न बनाए क्योंकि यहाँ इंसानी जिंदगी दांव पर लगी है।ष उन्होंने आगे कहा, ष्अपनी गलती मानना घ्कमजोरी की निशानी नहीं है। यह समझदारी, जवाबदेही और अपनी गलती सुधारने की इच्छा की निशानी है। हम बस जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। सीजेपी के अनुसार, उस दिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में **AAP** के एक प्रतिनिधिमंडल ने विरोध स्थल का दौरा किया और आंदोलन के प्रति एकजुटता व्यक्त की। **CPI(M)** सांसद अमरा राम ने भी आंध्र प्रदेश और राजस्थान के वरिष्ठ **CPI(M)** नेताओं के साथ स्थल का दौरा किया और मांगों का समर्थन किया। दौरा करने वाले नेताओं ने २० जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक प्रस्तावित शांतिपूर्ण मार्च का भी समर्थन किया। **CJP** के अनुसार, **AAP** के प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन के लिए अपना समर्थन दोहराया, एक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली की मांग की, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया। **CPI(ML)** लिबरेशन से जुड़ी 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन' **(AISA)** के सदस्य – नेहा, मनीष, दीपक और आमीन – ने विरोध स्थल पर एक अलग मंच पर अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखी। एक बयान में **AISA** ने कहा कि आतिशी ने भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से मुलाकात की और लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताई, क्योंकि छात्र हफ्तों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे और सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। संगठन ने यह भी कहा कि भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की सेहत और बिगड़ गई है, लेकिन साथ ही जोर देकर कहा कि विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

बीच सुनवाई पहले जज पर फेंके कागज, फिर गाली देते हुए बोला- इसे CJI को दे देना, सुप्रीम कोर्ट में हाई-वोल्टेज ड्रामा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में नाटकीय हालात देखने को मिले, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपनी

याचिका पर सुनवाई के दौरान, खुद पेश हुए एक शिकायतकर्ता ने बेंच की तरफ कागजात फेंके और अपशब्द कहे। सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। यह घटना जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के सामने हुई। कोर्ट रूम का माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब याचिकाकर्ता ने जजों से बात करते हुए असामान्य रूप से आक्रामक लहजा अपनाया। शिकायतकर्ता ने अपनी दलीलों की शुरुआत में कहा कि माननीय न्यायिक सेवक, मैं आपको लखनऊ के एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता हूं। इस टिप्पणी से अचंभित होकर न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूछा कि आप मुझे आदेश दे रहे हैं? आप हमें आदेश दे रहे हैं? कोर्ट में जवाब देते हुए शिकायतकर्ता ने कहा कि मेरी तरफ से बस इतना ही है। सब कुछ रिकॉर्ड पर है। लाइवॉल के अनुसार, इसके कुछ ही देर बाद मामला तब और बढ़ गया जब याचिकाकर्ता ने अपने केस के कागजात हवा में उछाल दिए और आरोप है कि चीफ जस्टिस के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच का हिस्सा नहीं थे। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत दखल दिया और उन्हें कोर्टरूम से बाहर निकालकर स्थिति को सामान्य किया। इस पूरी घटना के दौरान बेंच शांत रही और उसने इस गुस्से भरी प्रतिक्रिया पर कोई जवाब नहीं दिया।

केंद्रीय सूचना आयोग का निर्देशः पेट्रोल उत्पादन और इथेनॉल मिश्रण के आंकड़े सार्वजनिक करे पेट्रोलियम मंत्रालय की इकाई

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पेट्रोलियम मंत्रालय की योजना इकाई पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। आयोग ने पीपीएसी को पेट्रोल के उत्पादन, आयात, इथेनॉल की खरीद, इसके मिश्रण और पेट्रोलियम क्षेत्र में होने वाले मुनाफे से जुड़े ऐतिहासिक आंकड़े सार्वजनिक करने को कहा है। यह कदम तब उठाया गया जब आयोग ने पाया कि एक आरटीआई आवेदक को पीपीएसी द्वारा केवल आंशिक सूचना उपलब्ध ा कराई गई थी। सूचना आयुक्त खुशवंत सिंह सेठी ने सुनवाई के दौरान पीपीएसी को निर्देश दिया कि वे इथेनॉल मिश्रण से संबंधित अधिसूचनाओं के लिए विशिष्ट वेब लिंक प्रदान करें। इसके अलावा, इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े सवालों को संबंधित लोक प्राधिकरण को भेजने और कंपनी-वार पेट्रोल आपूर्तिकर्ताओं की जानकारी के मामले में आरटीआई कानून के तहत उचित छूट का स्पष्ट उल्लेख करने का भी आदेश दिया गया है। आरटीआई आवेदन के जरिए देश में पेट्रोल और इथेनॉल कार्यक्रम से जुड़ी छह महत्वपूर्ण श्रेणियों में जानकारी मांगी गई थी। इनमें ईंधन का उत्पादन, आयात, इथेनॉल मिश्रण के मानक, इसकी खरीद और खपत, आपूर्तिकर्ताओं का ब्योरा और पेट्रोल की बिक्री से होने वाला मुनाफा शामिल था। आयोग ने स्पष्ट किया कि चूंकि प्रतिवादी ने अब तक केवल आंशिक जानकारी ही दी है, इसलिए अब विभिन्न बिंदुओं पर संशोधित जवाब देना जरूरी

है। आवेदन में साल २०१४-१५ से पेट्रोल की खरीद, आयात और घरेलू उत्पादन के साथ-साथ इन पर होने वाले सालाना खर्च का स्रोत-वार विवरण मांगा गया था। पीपीएसी ने पहले तर्क दिया था कि सामान्य आंकड़े वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, लेकिन कंपनी-विशेष की जानकारी व्यावसायिक और गोपनीय है जिसे आरटीआई अधिनियम की धारा ८(१)(डी) और ८(१)(ई) के तहत छूट प्राप्त है। हालांकि, जब आवेदक ने कहा कि वह वेबसाइट पर ये आंकड़े नहीं खोज पा रहे हैं, तो आयोग ने पीपीएसी को सभी उपलब्ध सूचनाओं की सॉफ्ट कॉपी सीधे आवेदक के ई-मेल पर भेजने का आदेश दिया। इसी तरह इथेन ल मिश्रण के मानदंडों और सरकारी अधिसूचनाओं के मामले में भी आयोग ने पीपीएसी को विशिष्ट वेबसाइट लिंक देने को कहा है। पीपीएसी ने बताया कि यह नियमन राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति २०१८ के तहत आता है। वहीं इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं की सूची के बारे में जानकारी न होने पर, आयोग ने इस बिंदु को संबंधित लोक प्राधिकरण के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया, जो इस जानकारी का संरक्षक है। अंत में, पेट्रोल बिक्री से होने वाले मुनाफे और लाभ मार्जिन की गणना के संबंध में भी आयोग ने ऐतिहासिक डेटा ई-मेल के माध्यम से साझा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने पीपीएसी को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में किसी भी जानकारी से इनकार करते समय आरटीआई अधिनियम, २००५ की संबंधित छूटों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए नया जवाब जारी किया जाए।

बिल्डर ने ज्यादा जीएसटी वसूली है तो वापस मिलेगा पैसा, घर खरीदार ऐसे करें रिफंड क्लेम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने कहा है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं में जीएसटी की वसूली केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार ही की जानी चाहिए। हालांकि, रेरा के संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें परियोजनाओं के आवंटियों से निर्धारित दर से अधि ाक जीएसटी वसूली गई। रेरा के अनुसार, ऐसे घर खरीदारों को राहत देने के लिए राज्य कर विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। विभाग की अ नलाइन व्यवस्था के माध्यम से पात्र आवंटी अतिरिक्त भुगतान की गई जीएसटी राशि वापस पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। रेरा के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति ने फ्लैट खरीदा हो या भवन निर्माण के दौरान जीएसटी का भुगतान किया हो, लेकिन बाद में परियोजना निरस्त हो जाए, आवंटन रद्द हो जाए या अनुबंध समाप्त हो जाए और उस समय तक प्रमोटर के लिए क्रेडिट नोट जारी करने की वैध ानिक समय-सीमा खत्म हो चुकी हो, तो ऐसी स्थिति में आवंटी सीधे जीएसटी विभाग से रिफंड का दावा कर सकता है। रिफंड का दावा अनुबंध निरस्त होने या समाप्त होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर करना होगा। हालांकि, १,००० रुपये से कम जीएसटी राशि के मामलों में रिफंड का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। रेरा ने दोहराया है कि बिल्डर या प्रमोटर केवल केंद्र सरकार द्वारा तय जीएसटी दरों के अनुसार ही कर की वसूली कर सकते हैं। यदि किसी आवंटी से इससे अधिक

जीएसटी वसूली गई है और वह निध ारित शर्तों को पूरा करता है, तो उसे अतिरिक्त राशि वापस पाने का अधिकार है। रेरा के अनुसार, अपंजीं त आवंटी को सबसे पहले अपने पैन कार्ड के आधार पर जीएसटी पोर्टल पर अस्थायी पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद **'Refund for Unregistered Person'** श्रेणी के तहत फॉर्म **GST RFD** में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जीएसटी भुगतान का प्रमाण, आवश्यक दस्तावेज और प्रमोटर द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण-पत्र भी संलग्न करने होंगे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सक्षम अधिकारी लागू जीएसटी प्रावधानों के अनुसार पात्रता के आधार पर रिफंड मंजूर करेगा।

दो साल से एक शिक्षक के सहारे चल रहा प्राथमिक विद्यालय अकठी, १४४ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

ग्रामीणों ने सहायक अध्यापक की तैनाती की उठाई मांग,एक्जिक्यूटिव ब्रांच

धौरहरा खीरी। शिक्षा विभाग की लापरवाही का खामियाजा रमियाबेहड़ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अकठी के नौनिहाल भुगत रहे हैं।विद्यालय में करीब दो वर्ष से शिक्षकों की कमी बनी हुई है, जिसके चलते १४४ बच्चों की पढ़ाई मात्र एक शिक्षक के भरोसे चल रही है।इससे पठन–पाठन के साथ विद्यालय की अन्य शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापिका संगीता देवी को विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित न रहने के आरोप में करीब दो वर्ष पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ने निलंबित कर दिया था। निलंबन के बाद उन्हें ब्लाक के दलराजपुर विद्यालय से संबद्ध अटैच कर दिया गया।इसके बाद प्राथमिक विद्यालय अकठी में केवल प्रधानाध्यापक राघवेंद्र मिश्रा ही रह गए। जो अकेले ही १४४ विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ–साथ मिड–डे मील, नामांकन, अभिलेखों का रखरखाव एवं अन्य विभागीय कार्यों का दायित्व निभा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक शिक्षक के लिए सभी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना और विभागीय दायित्वों का निर्वहन करना बेहद कठिन है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि यदि शीघ्र ही सहायक अध्यापक की तैनाती नहीं की गई तो शिक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावित होगी। गांव के मनमोहन अवस्थी, बलभद्र, श्रीकांत, नारायन तिवारी, रूप कुमार, नमन, लालू, लीलाधर, संतोषी सहित अन्य ग्रामीणों ने बीएसए से विद्यालय में तत्काल सहायक अध्यापक की तैनाती की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि निलंबित सहायक अध्यापिका संगीता देवी को विभाग बहाल करता है तो उन्हें पुनः विद्यालय में तैनात किया जाए।अन्यथा बहाली होने तक किसी अन्य सहायक अध्यापक की नियुक्ति कर समस्या का समाधान कराया जाए।ताकि विद्यालय में पठन–पाठन की व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके।

ओयल जिला अस्पताल में लिफ्ट खराब, मरीजों और बुजुर्ग तीमारदारों की फूली सांसें, भारी परेशानी

लखीमपुर खीरी। जिला अस्पताल मोतीपुर (ओयल) में पिछले दो दिनों से लिफ्ट खराब होने के कारण मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर पहुंचने के लिए लोगों को सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे गंभीर मरीजों और बुजुर्गों की हालत खस्ता हो रही है।रविवार के बाद सोमवार को भी राहत नहीं मिली,अस्पताल परिसर में लगी लिफ्ट अचानक खराब हो गई। रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण तीमारदारों को उम्मीद थी कि सोमवार को स्थिति में सुधार होगा। हालांकि सोमवार को भी लिफ्ट बंद रही। इसके चलते वार्डों में भर्ती मरीजों की देखरेख करने वाले लोगों को दिनभर सीढ़ियों

से ही चक्कर काटने पड़े। तीसरी मंजिल पर भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने बताया कि दवा, भोजन और जांच रिपोर्ट के लिए उन्हें बार–बार नीचे–ऊपर आना पड़ता है। सीढ़ियों से लगातार चढ़ने–उतरने के कारण लोगों की सांसें फूल रही हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल बुजुर्गों और दिव्यांगों का है, जिन्हें मजबूरी में भारी परेशानी उठाकर ऊपर जाना पड़ रहा है। अस्पताल में आने वाले तीमारदारों का कहना है कि इतने बड़े जिला अस्पताल में लिफ्ट जैसी आवश्यक सेवा का दो दिनों तक ठप रहना प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है। गंभीर स्थिति वाले मरीजों को स्ट्रेचर या व्हीलचेयर से सीढ़ियों के रास्ते ऊपर ले जाना बेहद जोखिम भरा और कष्टदायक साबित हो रहा है। लोगों ने अस्पताल प्रशासन से जल्द से जल्द लिफ्ट को ठीक कराने की मांग की है।

सार्वजनिक जगहों पर पोर्नोग्राफी रोक की याचिका खारिज, सुप्रीम कोट बोला– ये पॉलिसी सरकार बनाएगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक **PIL** (जनहित याचिका) खारिज कर दी, जिसमें केंद्र सरकार से सार्वजनिक जगहों पर पोर्नोग्राफी देखने पर रोक लगाने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला पॉलिसी से जुड़ा है और याचिकाकर्ता से कहा कि वे सरकार के अधिकारियों के पास अपनी बात रखें। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने कहा कि यह मुद्दा अहम तो है, लेकिन इसमें कानून का ऐसा कोई सवाल शामिल नहीं है जिस पर कोर्ट को विचार करने की जरूरत हो। याचिका में पोर्नोग्राफी देखने पर रोक लगाने के लिए एक राष्ट्रीय प लिसी और एक्शन प्लान की मांग की गई थी, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी बालिग नहीं हुए हैं, और साथ ही सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह का पोर्नोग्राफिक मटीरियल देखने पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। बेंच ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि उठाया गया मुद्दा बहुत अहम है। हालांकि, इस मामले में कानून से जुड़ा ऐसा कोई सवाल नहीं है जिस पर इस कोर्ट को विचार करने की जरूरत हो। यह पॉलिसी से जुड़ा मामला है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी में तरक्की और एक्सपर्ट्स की राय की जरूरत है। ऐसे मामले एक्सपर्ट्स, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फ मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट सोशल वर्कर बीएल जैन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिनकी तरफ से वकील वरुण ठाकुर पेश हुए थे। याचिका में कहा गया इंटरनेट पोर्नोग्राफी के आंकड़े चौंकाने वाले हैंय हर सेकंड ५,००० पोर्न साइट्स देखी जाती हैं। इंटरनेट के जरिए २ करोड़ से ज्यादा पोर्न वीडियो/क्लिप्स जारी किए जा रहे हैं। कानून का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, २००० की धारा **69A** के तहत, प्रतिवादियों के पास किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स के जरिए किसी भी जानकारी तक जनता की पहुँच को रोकने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है। इसमें यह भी तर्क दिया गया कि इंटरनेट की व्यापक उपलब्धता ने पोर्नोग्राफिक कंटेंट को आसानी से उपलब्ध करा दिया है, जिससे इसका अत्यधिक सेवन और लत लग गई है। याचिका में दावा किया गया कि ऐसे कंटेंट के बढ़ते सेवन ने यौन अपराधों को बढ़ावा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले को सरकार के सामने उठाया जाना चाहिए, जबकि याचिका में एक राष्ट्रीय नीति, एक एक्शन प्लान और सार्वजनिक जगहों पर पोर्नोग्राफी देखने से रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की गई थी।

ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने पर उच्च न्यायालय ने उठाए संवैधानिक सवाल

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निर्वाचित ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के प्रावधान पर महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल उठाए हैं। अदालत ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा १२(३–ए) की संवैधानिक वैधता की जांच की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति राजन र य और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने संजय कुमार शर्मा की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। पीठ ने राज्य सरकार का पक्ष समझने के लिए पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को १० जुलाई को वीडियो क न्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि प्रेम लाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (२०००) मामले में एक समन्वय पीठ ने इसी तरह के एक वैधानिक प्रावधान को रद्द कर दिया था। अदालत ने उस समय माना था कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद '२४३–ई' और '२४३–के' के तहत पंचायतों के कार्यकाल और राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में दायर अपील का निपटारा करते हुए कानून से जुड़े सवालों को एक उचित मामले में विचार के लिए खुला छोड़ दिया था। उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह

महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल उठता है कि क्या निवर्तमान ग्राम प्रधान को प्रशासक नियुक्त करने से निर्वाचित पंचायत का कार्यकाल संवैधानिक रूप से निर्धारित अवधि से आगे प्रभावी रूप से बढ़ जाता है। अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या ऐसी व्यवस्था पंचायत चुनाव समय पर कराने के राज्य निर्वाचन आयोग के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करती है। पीठ ने इन मुद्दों के महत्व को देखते हुए निर्देश दिया कि मामले को इसी तरह के सवालों से संबंधित अन्य लंबित जनहित याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया जाए। अदालत ने राज्य सरकार से निर्वाचित निकाय का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पूर्व ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में बनाए रखने के कानूनी आधार और संवैधानिक औचित्य को स्पष्ट करने को भी कहा है।

सांप के काटने से युवक की मौत पर जिला अस्पताल में हंगामा, ४ घंटे बाधित रही इमरजेंसी सेवा

लखीमपुर खीरी। जनपद के थाना कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत महेवागंज के ग्राम ज्ञानपुर में सांप के काटने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल

मोतीपुर (ओयल) की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए भारी हंगामा किया। परिजनों के उग्र प्रदर्शन के कारण अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं करीब चार घंटे तक पूरी तरह बाधित रहीं, जिससे परिसर में अफरा–तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार, ज्ञानपुर निवासी दिनेश कुमार के पुत्र रंजीत कुमार (मृतक) को सांप ने काट लिया था। परिजन उसे आनन–फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल मोतीपुर ओयल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात ड क्टर ने इलाज में घोर लापरवाही बरती, जिसके कारण रंजीत की जान चली गई। युवक की मौत से आक्रोशित परिवार वालों और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में ही धरना दे दिया और हंगामा शुरू कर दिया। सीएमओ के आश्वासन और कार्रवाई के बाद शांत हुए परिजन अस्पताल में बवाल की सूचना मिलते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. संतोष गुप्ता एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। सीएमओ ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की बात और उचित जांच के भरोसे के बाद ही परिजन शांत हुए। काफी समझाने–बुझाने के बाद परिवार के लोग मृतक के शव का पोस्टमार्टम (पीएम) कराने के लिए राजी हुए।पुलिस बल ने संभाला

रंगमंच व वेबसीरीज के क्षेत्र में हाथरस के बच्चे अब स्थापित करेंगे नया कीर्तिमान- सदर विधायक अंजुला माहौर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी (संस्कृति विभाग) लखनऊ द्वारा हाथरस में भारतीय नाट्य विधा के संरक्षण हेतु आयोजित १५ दिवसीय नाद– प्रवाहः २०२६ प्रशिक्षण–शिविर का भव्यता पूर्वक हुआ समापन। शहर के लक्ष्मी नगर

स्थित सेन्ट आर. एच. कॉन्वेन्ट स्कूल में ३८ बच्चों ने सीखे भारतीय नाट्यविधा के गुण। हाथरस। ९ रंगमंच के क्षेत्र में पं. नथाराम गौड़ व काव्य विधा में काका हाथरसी ने जिस प्रकार हाथरस को विश्वपटल पर स्थापित किया था उसी प्रकार अब हाथरस के बच्चे रंगमंच व वेबसीरीज के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया इतिहास रचेंगे साथ ही हाथरस में विजय दशमी के अवसर पर बच्चों द्वारा कराई जाएगी परम्परागत रूप से रामलीला' उक्त वक्तव्य के द्वारा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी (संसेंति विभाग) लखनऊ व ब्रज संस्कृति केन्द्र, हाथरस (रजि.) द्वारा संयुक्त रूप से हाथरस में भारतीय नाट्य विधा के संरक्षण हेतु १५ दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सदर विधायक माननीया अंजुला माहौर ने सभी ३८ प्रतिभागी बच्चों का उत्साह वर्धन कर उनके उज्ज्वल भविष्य हेतु वैश्विक स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करने के महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोकनाट्यविद आचार्य डॉ. खेमचन्द यदुवंशी शास्त्री ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा शिक्षा में रंगमंच के महत्व को प्रतिपादित करते हुए हाथरस को रंगमंच के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से जनपद के चयनित बच्चों को रंगमंच की बारीकियों का प्रशिक्षण देकर पारंगत बनाया गया है जिससे वह रंगमंच व वेबसीरीज के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर सकें। विधायक अंजुला माहौर व अन्य अतिथियों ने माँ सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन करते हुए बाल–कलाकारों को प्रशस्ति–पत्र प्रदान करते हुए सम्मानित कर शुभाशीर्वाद प्रदान किया। दीपक गिरि, उर्वशी वर्मा, दिव्यांशी वर्मा, करिश्मा कुशवाहा, नंदिनी गौड़, पायल गौड़, मनीषा वार्ष्णेय, भव्य शर्मा, इशिता शर्मा, पुनीत उपाध्याय, ऋचा उपाध्याय, वैभव शर्मा, करन वर्मा, प्रिन्सी चौधरी, ध्रुव चौधरी, साक्षी उपाध्याय, आयुष वर्मा, कार्तिक शर्मा, सक्षम उपाध्याय, सागर उपाध्याय, मोहित गौड़, प्रद्युम्न यादव, राखी कुमारी, ऋतुराज यादव, सूरज कुमार, अनिल कुमार, सत्य प्रकाश, अनामिका सिंह, कुँवर भुवनेंद्र सिंह, अयान अली, प्रदीप कुमार, जतिन कुमार, आर्वी गुप्ता, गुड्डन कुमारी, ऋतु चौधरी, कन्हैया लाल, मोहिनी भास्कर,कपिल कुशवाहा आदि। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक एडवोकेट अजय किशोर गौड़ द्वारा की गई। इस अवसर पर अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय आशुकवि पं. अनिल बोहरे तथा विशिष्ट अतिथि रहे व्यापार फैडरेशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल,शिक्षाविद प्रमिला गौड़, संस्कार भारती हाथरस के अध्यक्ष चौतन्य प्रकाश उपाध्याय,सुकवि गाफिल स्वामी तथा सभासद मूलचन्द वार्ष्णेय। इस अवसर पर प्रशिक्षार्थियों के अभिभावक व क्षेत्रीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन ऋचा उपाध्याय व राशि वार्ष्णेय ने संयुक्त रूप से किया तथा उप प्रधानाचार्य मोहित गौड़ ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

शनि देव का द्वितीय स्थापना दिवस मनाया गया

बरवर। शनिदेव मंदिर की मूर्ति द्वितीय स्थापना दिवस के बहुत ही धूमधाम से मनाया गया इस पावन बेला पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया शनि

देव की श्रृंगार पूजा हवन व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें शनि देव भंडारा आयोजन समिति की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गयाशनि देव समिति के संरक्षक एडवोकेट धीरेंद्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष एडवोकेट विमल शुक्ला, कोषाध्यक्ष सतपाल कुशवाहा संरक्षक नगर पंचायत अध्यक्ष संजय शर्मा ,नीरज कुशवाहा, प्रदीप पाल, धर्मेश पाल, लाखन, श्रीदेवी स्थान प्रबंध समिति अध्यक्ष धर्मेश शर्मा, भावना शर्मा ,बीरबल कुशवाहा, श्री गरीब दास जी, सत्यपाल कुशवाहा, मनोज दीक्षित, अभिलाष गुप्ता, प्रवीण दीक्षित .आनंद पाण्डेय ,माता राम मुनेश्वर दयाल ,ठाकुरपाल , जयपाल प्रशांत शर्मा. पण्डित नरेंद्र, सुभाष पांडे, एडवोकेट प्रशांत पांडे, कुलदीप राजपूत, नितिन द्विवेदी, रविशंकर शुक्ल, योगेश मिश्रा युग, राम जी मिश्रा, दिवाकर नाथ मिश्रा, रघुवीर कुशवाहा,समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे।

सेवा और सम्मान के संकल्प के साथ नवदिशा की नई टीम ने संभाली कमान

लखीमपुर खीरी। इनर व्हील क्लब लखीमपुर नवदिशा का वर्ष २०२५–२६ का अवॉर्ड समारोह एवं वर्ष २०२६–२७ का इंस्ट लेशन समारोह भव्यता के साथ आयोजित

हुआ। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष ईरा श्रीवास्तव रहीं। निवर्तमान अध्यक्ष (आईपीपी) दीपाली गुप्ता ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए वर्षभर संचालित सेवा प्रकल्पों की जानकारी दी। इस दौरान सहयोगी सदस्यों एवं प्रेस प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद नई कार्यकारिणी का विधिवत पदभार ग्रहण समारोह हुआ। निवर्तमान पदाधिकारियों ने नए पदाधिकारियों को पद की पिन पहनाकर दायित्व सौंपे। आईपीपी दीपाली गुप्ता ने नव निर्वाचित अध्यक्ष नीतू अग्रवाल को अध्यक्षीय कलर पहनाई, इसके उपरांत अध्यक्ष नीतू अग्रवाल ने अपनी वर्ष २०२६–२७ की पूरी टीम का परिचय उपस्थित अतिथियों एवं सदस्यों से कराया। सभा में उपस्थित सभी नवदिशा सदस्यों एवं अतिथियों को एक–एक पौधा भी भेंट किया गया। 'एक पौधा माँ के नाम' अभियान को आगे बढ़ाते हुए नीतू अग्रवाल ने सभी से पौधे अपने घरों में रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। समारोह में शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एक छात्र को लैपटॉप तथा हाईस्कूल में लखीमपुर जनपद में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन पूजा निगम ने प्रभावशाली ढंग से किया। कुमकुम गुप्ता, सपना कक्कड़, विभा सक्सेना, मनजीत कौर सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। अपने अध्यक्षीय संबोधन में नीतू अग्रवाल ने कहा कि सभी सदस्यों के सहयोग से नवदिशा सेवा, शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छुएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि टीम भावना और समर्पण के बल पर क्लब समाजहित के और भी अधिक प्रभावी कार्य करेगा।

पेट्रोल–डीजल चोरी के नेटवर्क का पर्दाफाश, पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने उगले कई अहम राज

लखनऊ। पेट्रोल–डीजल चोरी के नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस की पूछताछ में आरोपी अनिल विश्वकर्मा ने कई अहम राज उगले हैं। पूछताछ में उसने बताया कि वह पहले हाईवे किनारे पान की दुकान चलाता था। दुकान पर अक्सर पेट्रोल और डीजल से भरे टैंकर रुकते थे। इसी दौरान उसकी टैंकर चालकों और परिवहन से जुड़े अन्य लोगों से अच्छी जान–पहचान हो गई। यही पहचान के बाद पेट्रोल–डीजल चोरी के नेटवर्क की नींव पड़ी थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बताया कि शुरुआत में वह मौका मिलने पर टैंकरों से पांच से छह लीटर पेट्रोल व डीजल निकालकर चोरी से बेचता था। धीरे–धीरे टैंकर चालकों से उसके संबंध मजबूत होते गए और उसने इस अवैध धंधे को बड़े स्तर पर अंजाम देना शुरू कर दिया। पिछले छह महीने के दौरान उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर पेट्रोल–डीजल चोरी और उसमें मिलावट का गिरोह तैयार कर लिया। मास्टर चाबी से खोलते थे टैंकर पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में पता चला कि आरोपी के कब्जे से बरामद मास्टर चाबी पूरे गिरोह के लिए सबसे अहम हथियार थी। इसी मास्टर चाबी की मदद से डिपो से

पेट्रोल पंपों के लिए रवाना होने वाले टैंकरों के ताले खोले जाते थे। जबकि इन टैंकरों की मूल चाबी संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के पास रहती है। आरोपी बिना ताला तोड़े मास्टर चाबी से लॉक खोलता, ईंधन निकालता और फिर टैंकर को दोबारा बंद कर देता था, जिससे चोरी का आसानी से पता नहीं चल पाता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बरामद मास्टर चाबी को जब्त कर लिया है और उसका उल्लेख बरामदगी में किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अब यह पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क में टैंकर चालक, परिवहन से जुड़े अन्य लोग या किसी तेल कंपनी से जुड़े कर्मचारी की भूमिका तो नहीं रही। चोरी किए गए पेट्रोल–डीजल की सप्लाई किन लोगों तक पहुंचती थी और मिलावट का कारोबार कहां–कहां संचालित हो रहा था, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बड़े नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा।

आवश्यक सूचना

मैं प्रदीप कुमार सिंह, पुत्र स्वप्न उदय शंकर सिंह, निवासी ४४८/१३५६, झब्बन की बगिया, ठाकुरगंज, लखनऊ, का हूं। मेरा उत्तर प्रदेश टीईटी (प्राथमिक) २०१४ का अंकपत्र (मार्कशीट) दिनांक ०१.०७.२०२४ को वास्तव मे कहीं ,खो गया है। जिसका रोल नंबर २६१०३०१७३६ एवं पंजीकरण संख्या २६००२६६१५५ है। यदि किसी को उक्त अंकपत्र मिले तो कृपया मोबाइल नंबर ७०५४२२२२२८ पर सूचित करें। सूचना देने वाले का आभारी रहूँगा।

प्रदीप कुमार सिंह,
पुत्र स्वप्न उदय शंकर सिंह,
निवासी ४४८/१३५६, झब्बन की बगिया, ठाकुरगंज, लखनऊ।

साइबर में ठगी में इंडियन बैंक और एसबीआई के सबसे ज्यादा म्यूल खाते

लखनऊ। साइबर अपराध में रविवार को एक बड़े गिरोह का खुलासा किया गया। इसके नौ सदस्य दबोचे गये। वहीं दो मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह म्यूल अकाउंट (किराये के बैंक खातों) नेटवर्क का बड़ा गिरोह है। कार्रवाई के दौरान विभिन्न बैंकों के ५० एटीएम/डेबिट–क्रेडिट कार्ड, कई पासबुक और चेकबुक बरामद की गई हैं। जांच में सामने आया कि बरामद बैंक खातों का इस्तेमाल देशभर में होने वाली साइबर ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए किया जा रहा था। इसमें सबसे अधिक इंडियन बैंक व एसबीआई के म्यूल खाते खुलवाये गये। इन दोनों बैंकों में १५ खातों की डिटेल पुलिस के हाथ लगी है। जिनका प्रयोग साइबर ठगी में किया गया है। पुलिस के अनुसार, बरामद एटीएम कार्डों में सबसे अधिक इंडियन बैंक के आठ, एसबीआई के सात, एक्सिस बैंक के चार कार्ड मिले। इसके अलावा पीएनबी के चार, बैंक ऑफ बड़ौदा के तीन, एचडीएफसी के तीन, बंधन बैंक के तीन, आईसीआईसीआई के दो, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक व कोटक महिंद्रा के दो–दो, फेडरल बैंक, आरबीएल, आईडीएफसी, जीओ बैंक, एयू स्माल फाइनेंस बैंक, आईडीबीआई बैंक, नैनीताल बैंक, फिनो बैंक्र केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्रा के एक–एक खाते मिले हैं। इन खातों की जांच की जा रही है। इसे खुलवाने में किन कर्मचारियों व अधिकारियों की भूमिका रही। इसकी भी जांच शुरू हो गई। इनमें कुछ खाते मोहम्मद शोएब तथा आजम खान के नाम पर संचालित पाए

गए। एडीसीपी क्राइम किरन यादव के मुताबिक, बरामद खातों की जांच राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर की गई। जिसमें सामने आया कि कई खातों पर पहले से साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज मिलीं। इंडियन बैंक के खाते पर दो, एचडीएफसी बैंक के खाते पर तीन, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के खाते पर एक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के खाते पर एक तथा एचडीएफसी बैंक के एक अन्य खाते पर दो शिकायतें दर्ज पाई गईं। इससे स्पष्ट हुआ कि इन खातों का इस्तेमाल साइबर अपराध में किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पैसों का लालच देकर उनके बैंक खाते, पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और बैंकिंग क्रेडेंशियल अपने कब्जे में ले लेता था। इसके बाद इन खातों की जानकारी टेलीग्राम के माध्यम से विदेशी, विशेष रूप से चीनी साइबर ठगों तक पहुंचाई जाती थी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी टेलीग्राम और डिजिटल वॉलेट के जरिए खातों की जानकारी, ट्रांजैक्शन और अन्य संवेदनशील सूचनाओं का आदान–प्रदान करते थे। समय–समय पर चौट और डिजिटल साक्ष्य भी डिलीट कर देते थे। इसी आशंका के चलते आरोपियों को हिरासत में लिया गया, ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट न कर सकें। साइबर ठगी की रकम इन खातों में आने के बाद आरोपी एटीएम और चेकबुक के जरिए नकदी निकाल लेते थे। इसके बाद अपना कमीशन काटकर शेष रकम साथियों की मदद से यूएसडीटी में परिवर्तित कर डिजिटल वॉलेट के माध्यम से विदेशी ठगों को भेज दी जाती थी। पुलिस अब पूरे नेटवर्क, अन्य सहयोगियों और विदेशी कनेक्शन की जांच कर रही है।

शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख

लखनऊ। चौक के अकबरी गेट स्थित अहमद हुसैन अपार्टमेंट में सोमवार शाम को बिस्कुट व नमकीन की दुकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही चौक फायर

स्टेशन से चार गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद एक घंटे में आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। सीएफओ अंकुश मित्तल के मुताबिक शाम करीब ५रू४६ बजे आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद चौक फायर स्टेशन प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आग दुकान के अंदर तेजी से फैल रही थी। दमकल कर्मियों ने एक ओर से होज लाइन बिछाकर आग बुझाने का काम शुरू किया, जबकि दूसरी ओर से बीए सेट (ब्रीदिंग अपरेटस) पहनकर जवानों को दुकान के भीतर भेजा गया। साथ ही दो अन्य दमकल गाड़ियों से रिले पंपिंग के जरिए लगातार पानी की आपूर्ति कर आग बुझाई गई। करीब एक घंटे के अभियान के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। आग अतीक की बिस्कुट–नमकीन की दुकान में लगी थी। अतीक कैसरबाग के घसियारी मंडी क्षेत्र का निवासी है। शुरूआती जांच में सामने आया कि आग शार्ट सर्किट से लगी है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं, आग से दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर नष्ट हुआ है।

'बंटवारा १९४७' का नया पोस्टर रिलीज

मुम्बई। सनी देओल अभिनीत आगामी ऐतिहासिक फिल्म 'बंटवारा १९४७' का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है। इससे पहले रिलीज हुए फिल्म के टीजर को दर्शकों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी

और अब मेकर्स नें ष्ण के किरदार की पहली झलक साझा कर फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है फिल्म के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्टर साझा करते हुए लिखा, "जब दुनिया ने अपने–अपने पक्ष चुन लिए, तब उसने धर्म का रास्ता चुना। इस पार्टिशन डे, १४ अगस्त को सिनेमाघरों में देखिए बंटवारा १९४७" 'बंटवारा १९४७' भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक ऐतिहासिक ड्रामा है। फिल्म १९४० के दशक के उस दौर की कहानी को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करती है, जब देश के विभाजन ने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया था। फिल्म में भय, विस्थापन और बिछड़ने की त्रासदी के बीच साहस, मानवता और नैतिक मूल्यों को प्रमुखता से दिखाया गया है। फिल्म में सनी देओल के साथ शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है। फिल्म का संगीत ए. आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। फिल्म का निर्माण आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने किया है। 'बंटवारा १९४७' १४ अगस्त २०२६ को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'जुरासिक पार्क' अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की उम्र में निधन

मुम्बई। हॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता और 'जुरासिक पार्क' तथा 'द पियानो' जैसी चर्चित फिल्मों में अपनी दमदार अभिनय क्षमता के लिए चर्चित सैम नील का निधन हो गया। वह ७८ वर्ष के थे। नील का सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में निधन हो गया। उनके आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर जारी बयान में कहा गया कि उनका निधन "अचानक और अप्रत्याशित" था। बयान के अनुसार, निधन के समय वह कैंसर से पीड़ित नहीं थे। हालांकि, मौत के कारण का खुलासा नहीं किया गया है। परिवार ने कहा, "सैम अपने परिवार के बीच थे और उन्होंने उसी गरिमा के साथ अंतिम सांस ली, जिसने उनके पूरे जीवन को परिभाषित किया। नील ने वर्ष २०२३ में खुलासा किया था कि उन्हें एंजियोइम्यूनोब्लास्टिक टी–सेल लिंफोमा नामक दुर्लभ प्रकार के न न–ह जकिन लिंफोमा का पता चला था। साल १९४७ में उत्तरी आयरलैंड में जन्मे श्री नील का मूल नाम निगेल नील था। सात वर्ष की उम्र में उनका परिवार न्यूजीलैंड चला गया। उन्होंने बाद में 'सैम' नाम अपनाया क्योंकि उनके स्कूल में निगेल नाम के कई छात्र थे। उनका परिवार दक्षिण द्वीप के डुनेडिन में बस गया और उनकी पढ़ाई क्राइस्टचर्च के बोर्डिंग स्कूल में हुई। नील ने १९७७ में न्यूजीलैंड की फिल्म स्लीपिंग डॉग्स से मुख्य अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। यह एक दशक से अधिक समय बाद बनी न्यूजीलैंड की पहली फीचर फिल्म थी। उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान १९७९ में गिलियन आर्मस्ट्रांग निर्देशित माय ब्रिलियंट करियर से मिली। इसके बाद उन्होंने डेड काल्म, स्वीट रिवेंज,

द पियानो और इवेंट होराइजन जैसी फिल्मों में विविध भूमिकाएं निभायीं। उन्हें सबसे अधिक लोकप्रियता १९९३ की ब्लॉकबस्टर फिल्म जुरासिक पार्क में पुराजीव विज्ञानी ड . एलन ग्रांट की भूमिका से मिली। फिल्म में उन्होंने ल रा डर्न, जेफ गोल्डब्लम और रिचर्ड एटनबरो के साथ अभिनय किया। उन्होंने द लॉस्ट वर्ल्डरू जुरासिक पार्क (१९९७) में अभिनय नहीं किया, लेकिन जुरासिक पार्क III (२००१) और जुरासिक वर्ल्डः डोमिनियन (२०२२) में डॉ. ग्रांट की भूमिका में वापसी की। मार्च २०२३ में उनकी आत्मकथा डिड आई एवर टेल यू दिस? प्रकाशित हुई थी। फिल्म जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की स्वीकृति से उन्हें नाइटहुड की उपाधि भी प्रदान की गयी थी।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
संजय बाजपेई
सीतापुर
मो.9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
सुरेश नारायण मिश्र
क्षेत्रीय सम्पादक
सौरभ कुमार, बिहार
मो.09386075289
मो० अरशद
ब्यूरो चीफ
मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566

सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191.
9026560178

Email-
adbhutsamachar
@yahoo.in
adbhut_samachar
@rediffmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक